Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair means) Act, 1992

(Act No. 27 of 1992)

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992

(1992 का अधिनियम संख्यांक 27)

[Enactment Date: 08th Nov. 1992]

Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022

(Act No. 6 of 2022)

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 6)

[Enactment Date: 05th April, 2022]

Included

Practice MCQs

Sample Preview

Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

www.LinkingLaws.com

Index

S.No.	TOPIC	*Page No.*
1.	**Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair means) Act, 1992**	***A-1 – A-8***
2.	**Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022**	***B-1 – B-15***
3.	**Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair means) Act, 1992 -** Practice MCQs	***C-1 – C-8***
4.	**Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022 -** Practice MCQs	***D-1 – D-13***
5.	**QR Code** • **Scan QR** for **Landmark Judgments (Year wise & Subject wise)** • **Khallas Class**	***E-1 – E-2***

Sample Preview

THE
Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair means) Act, 1992

(Act No. 27 of 1992)

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992

(1992 का अधिनियम संख्यांक 27)

[Enactment Date: 08th Nov. 1992]

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992

Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair means) Act, 1992

ARRANGEMENT OF SECTIONS/ धाराओं का क्रम

S.No.	Section Heading	Page No.
1.	Short title, extent and commencement. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	A-4
2.	Definitions. / परिभाषाएं	A-4
3.	Prohibition of use of unfair means. अनुचित साधनों के प्रयोग का निषेध	A-4
4.	Unauthorised possession or disclosure of question paper. प्रश्न पत्र का अनाधिकृत कब्ज़ा या प्रकटीकरण करना	A-4
5.	Prevention of leakage by person entrusted with examination work. / परीक्षा कार्य सौंपे गए व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण का निवारण	A-4
6.	Penalty. / शास्ति	A-6
6A.	Punishment for committing theft, extortion or robbery of question papers प्रश्नपत्रों की चोरी, जबरन वसूली या डकैती करने पर दंड।	A-6
7.	Penalty for offence with preparation to cause hurt. उपहति कारित करने की तैयारी के साथ अपराध की शास्ति	A-6
8.	Power to amend Schedule. / अनुसूची संशोधन करने की शक्ति	A-6
	Schedule	A-8

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair means) Act, 1992

(Act No. 27 of 1992)

[08th Nov. 1992]

An Act to prevent the leakage of question papers and use of unfair means at public examinations and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-third Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.

(1) This Act may be called the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair means) Act, 1992.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.

In this Act, —

(a) "**examination centre**" means any place fixed for holding public examination and includes the entire premises attached thereto;

(b) "**public examination**" means any of the examination specified in the schedule;

(c) "**unfair means'** in relation to an examination while answering question in a public examination, means the unauthorised help from any person, or from any material written, recorded or printed, in any form whatsoever or the use of any unauthorised telephonic, wireless or electronic or other instrument or gadget; and

(d) the words and expressions used herein and not defined, but defined in the Indian Penal Code, have the meanings respectively assigned to them in that code.

3. Prohibition of use of unfairmeans.

No person shall use unfairmeans at any public examination.

4. Unauthorised possession or disclosure of question paper.

No person who is not lawfully authorised or permitted by virtue of his duties so to do shall, before the time fixed for distribution of question papers to examinees at a public examination—

(a) procure or attempt to procure or possess, such question paper or any portion or copy thereof; or

(b) impart or offer to impart, information which he knows or has reason to believe to be related to, or derived from or to have a bearing upon such question paper.

5. Prevention of leakage by person entrusted with examination work.

No person who is entrusted with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do, directly, or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him.

www.LinkingLaws.com

Sample Preview

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992

(1992 का अधिनियम संख्यांक 27)

[08th नवम्बर 1992]

सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के प्रकटीकरण को और अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए और उनसे संसक्त और उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तेतालीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1992 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में-

(क) "**परीक्षा-केन्द्र** " से, सार्वजनिक परीक्षा प्रायोजित करने के लिए नियत कोई भी स्थान अभिप्रेत है और उसमें उससे संलग्न सम्पूर्ण परिसर सम्मिलित है;

(ख) "**सार्वजनिक परीक्षा**" से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी परीक्षा अभिप्रेत है;

(ग) किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय परीक्षा के संबंध में "**अनुचित साधन**" का अर्थ, किसी भी व्यक्ति से या किसी भी लिखित, अभिलिखित या मुद्रित सामग्री से किसी भी रूप में अप्राधिकृत सहायता से या किसी टेलीफोन, वायरलेस या इलेक्ट्रोनिक या अन्य यंत्र या जुगत का अप्राधिकृत प्रयोग अभिप्रेत है;

(घ) इसमें प्रयुक्त किये गये और परिभाषित नहीं किये गये किन्तु भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वे अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः उस संहिता में समनुदेशित किये गये हैं ।

3. अनुचित साधनों के प्रयोग का निषेध

कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा ।

4. प्रश्न पत्र का अनाधिकृत कब्ज़ा करना या प्रकटीकरण

कोई भी व्यक्ति, जिसे अपने कर्तव्यों पालन के संबंध में ऐसा करने के लिए प्राधिकार अनुज्ञा विधिपूर्वक प्राप्त नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रश्नपत्र के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व-

(क) न तो ऐसे किसी प्रश्नपत्र या उसके किसी भाग या प्रतिलिपि को हस्तगत करेगा, न हस्तगत करने का प्रयास करेगा, न कब्जे में रखेगा; या

(ख) न ऐसी कोई सूचना किसी को देगा या देने का प्रस्ताव करेगा जिसके बारे में उसे जानकारी है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे प्रश्नपत्र से संबंधित, व्युत्पन्न या संदर्भित है।

5. परीक्षा कार्य सौंपे गए व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण का निवारण

कोई भी व्यक्ति जिस पर सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई भी कार्य सौंपा गया है, सिवाय वहां के जहां उसे ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात किया गया है, कोई भी ऐसी सूचना या उसका भाग, जो उसे सौंपे गए कार्य के आधार पर उसकी जानकारी में आया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो प्रकट करेगा और न प्रकट करवायेगा और न किसी भी अन्य व्यक्ति को बतायेगा ।

www.LinkingLaws.com

THE
RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION (MEASURES FOR PREVENTION OF UNFAIR MEANS IN RECRUITMENT) ACT, 2022

(Act No. 6 of 2022)

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 6)

[Enactment Date: 05th April, 2022]

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION (MEASURES FOR PREVENTION OF UNFAIR MEANS IN RECRUITMENT) ACT, 2022

ARRANGEMENT OF SECTIONS/ धाराओं का क्रम

S.No.	Section Heading	*Page No.*
1.	Short title, extent and commencement. / संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.	B-4
2.	Definitions. / परिभाषाएं	B-4
3.	Prohibition of use of unfair means. अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध.	B-6
4.	Possession and disclosure of question paper. प्रश्नपत्र का कब्जा और प्रकटीकरण.	B-6
5.	Prevention of leakage by person entrusted or engaged with examination work. परीक्षा कार्य से न्यस्त या उसमें लगे हुए व्यक्ति द्वारा प्रकटन की रोकथाम.	B-6
6.	Unauthorized possession or disclosure of question paper and answer sheet or OMR sheet in any form. प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक या ओ.एम.आर. शीट का किसी भी रूप में अप्राधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण.	B-6
7.	Prohibition to enter in examination center. परीक्षा केन्द्र में प्रवेश का प्रतिषेध.	B-6
8.	No place other than examination center shall be used for public examination. परीक्षा केन्द्र से भिन्न कोई स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लिया जायेगा	B-8
9.	Offences by Management, Institution or others. / प्रबंधतंत्र, संस्था या अन्य द्वारा अपराध.	B-8
10.	Penalties. / शास्तियां.	B-8
11.	Debarment on conviction. / दोषसिद्धि पर विवर्जन.	B-10
12.	Attachment and confiscation of property. संपत्ति की कुर्की और अधिहरण.	B-10
13.	Liability of Management etc. to pay all cost and expenditure. समस्त लागत और व्यय का संदाय करने का प्रबंधतंत्र इत्यादि का दायित्व.	B-10
14.	Offences to be Cognizable, non-bailable and non-compoundable. अपराधों का संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होना.	B-10
15.	Investigation of the offences. / अपराधों का अन्वेषण.	B-10
16.	Cases triable by Designated Courts. अभिहित न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामले.	B-12
17.	Power to appoint Designated Courts. अभिहित न्यायालयों को नियुक्त करने की शक्ति.	B-12
18.	Act not in derogation of any other law. अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना.	B-12
19.	Power to remove difficulties. / कठिनाइयों का निराकरण करने की शकति.	B-12
20.	Power to make rules. / नियम बनाने की शक्ति.	B-12
-	SCHEDULE-I / अनुसूची-1	B-14
-	SCHEDULE-II / अनुसूची-2	B-14

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION (MEASURES FOR PREVENTION OF UNFAIR MEANS IN RECRUITMENT) ACT, 2022

(Act No. 6 of 2022)

(Received the assent of the Governor on the 5th day of April, 2022)

An Act to provide for effective measures to prevent and curb the offences of leakage of question papers and use of unfair means at public examinations for the purpose of recruitment to any post under the State Government including autonomous bodies, authorities, boards or corporations, and to provide for designated courts for the trial of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.

(1) This Act may be called the Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.

In this Act, unless the subject or context otherwise requires,

(a) "**conduct of public examination**" means and includes preparation, printing, supervision, coding, processing, storing, transportation, distribution and collection of question papers, answer sheets, OMR sheets and result sheets, evaluation, declaration of result, etc;

(b) "**examination authority**" means an examination authority as specified in the Schedule-I;

(c) "**examination center**" means any institution or part thereof or any other place fixed and used for the holding of a public examination and includes the entire premises attached thereto;

(d) "**examinee**" means a person who has been granted permission by the concerning authority to appear in a public examination, and includes a person authorized to act as scribe on his behalf;

(e) "**public examination**" means examination for the purpose of recruitment to any post under the State Government including autonomous bodies, authorities, boards or corporations as specified in the Schedule-II;

(f) "**unfair means**" includes,-

(i) in relation to an examinee, to take unauthorized help in public examination from any person or group directly or indirectly or from any material written, recorded, copied or printed, in any form whatsoever, or use of any unauthorized electronic or mechanical instrument or gadget;

(ii) in relation to any person,-

I. to impersonate or leak or attempt to leak or conspire to leak question paper; or

Sample Preview
www.LinkingLaws.com

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 6)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अप्रेल, 2022 को प्राप्त हुई)

स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के प्रकटन और अनुचित साधनों के उपयोग के अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रभावी अध्युपायों का उपबंध करने के लिए और ऐसे अपराधों के विचारण के लिए अभिहित न्यायालयों, और उनसे संसक्त या आनुषंगिक मामलों, का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.

(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "**सार्वजनिक परीक्षा का संचालन**" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है प्रश्नपत्रों, उत्तर पत्रकों, ओ. एम.आर. शीट और परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण, पर्यवेक्षण, कोडिंग, प्रक्रिया, भंडारकरण, परिवहन, वितरण और संग्रहण, मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा, इत्यादि;

(ख) "परीक्षा प्राधिकारी" से अनुसूची- 1 में यथाविनिर्दिष्ट परीक्षा प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "परीक्षा केन्द्र" से किसी सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियत और प्रयुक्त कोई संस्था या उसका भाग या कोई अन्य स्थान अभिप्रेत है और इसमें उससे संलग्न संपूर्ण परिसर सम्मिलित है;

(घ) "परीक्षार्थी" से ऐसा व्यक्ति, जिसे सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, अभिप्रेत है और इसमें उसके निमित्त श्रुतलेखक के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति सम्मिलित है;

(ङ) "सार्वजनिक परीक्षा" से स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भर्ती के प्रयोजन के लिए अनुसूची- 2 में यथाविनिर्दिष्ट परीक्षा अभिप्रेत है;

(च) "अनुचित साधन" में,-

(i) किसी परीक्षार्थी के संबंध में, सार्वजनिक परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी रूप में किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रानिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग करना, सम्मिलित है;

(ii) किसी व्यक्ति के संबंध में,-

I. प्रश्नपत्र के प्रतिरुपण या प्रकटन या प्रकटन का प्रयास या प्रकटन का षडयंत्र करना; या

www.LinkingLaws.com
Sample Preview

II. to procure or attempt to procure or possess or attempt to possess question paper in unauthorized manner; or

III. to solve or attempt to solve or seek assistance to solve question paper in unauthorized manner; and

IV. directly or indirectly assist the examinee in the public examination in unauthorized manner.

Explanation.- Any person also includes an examinee; and

(g) the words and expressions used herein and not defined, but defined in the Indian Penal Code, 1860, shall have the same meanings respectively assigned to them in that code.

3. Prohibition of use of unfair means.

No person shall use unfair means at any public examination.

4. Possession and disclosure of question paper.

No person authorized by virtue of his duties in conduct of public examination shall before the time fixed for opening and distribution of question papers-

(a) open, leak or procure or attempt to procure, possess or solve such question paper or any portion or a copy thereof; or

(b) give any confidential information or promise to give such confidential information to any person or examinee, where such confidential information is related to or in reference to such question paper.

5. Prevention of leakage by person entrusted or engaged with examination work.

No person, who is entrusted or engaged with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do, directly or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him.

6. Unauthorized possession or disclosure of question paper and answer sheet or OMR sheet in any form.

No person who is not lawfully authorized or permitted by virtue of his duties to do so, shall, before the time fixed for the distribution of question papers-

(a) procure or attempt to procure or possess, such question paper or answer sheet or OMR sheet or any portion or copy thereof in any form; or

(b) impart or offer to impart, such information which he knows or has reason to believe to be related to, or derived from or to have a bearing upon such question paper.

7. Prohibition to enter in examination center.

No person who is not entrusted or engaged with the work pertaining to public examination or conduct of public examination or who is not an examinee, shall enter the premises of the examination center.

Sample Preview
www.LinkingLaws.com

1. What is the short title of Act No. 27 of 1992? अधिनियम संख्या 27, 1992 का संक्षिप्त शीर्षक क्या है?

(A) Rajasthan Examination Control Act, 1992 / राजस्थान परीक्षा नियंत्रण अधिनियम, 1992
(B) Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992
(C) Rajasthan Recruitment Examination Act, 1992
राजस्थान भर्ती परीक्षा अधिनियम, 1992
(D) Rajasthan Competitive Examination Act, 1992 / राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 1992

Ans: (B)

Explanation: Section 1(1) provides the short title of the Act. It is officially called the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992. The title itself reflects the legislative intent — to prevent leakage of question papers and unfair practices in public examinations. This ensures transparency and credibility in recruitment and academic processes.

स्पष्टीकरण: धारा 1(1) अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक बताती है। इसका आधिकारिक नाम है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992। शीर्षक ही विधायी उद्देश्य को दर्शाता है — प्रश्नपत्रों की लीक और अनुचित साधनों की रोकथाम। इससे भर्ती और शैक्षिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

2. When does the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992 come into force? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 कब लागू होता है?

(A) From the date of Governor's assent
राज्यपाल की स्वीकृति की तिथि से
(B) From the date of Gazette publication
राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से
(C) At once / तत्काल लागू होता है
(D) From the date notified by State Government
राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से

Ans: (C)

Explanation: Unlike many Acts which require a government notification for commencement, Section 1(3) of this Act states that it shall come into force at once. This reflects the urgency of the legislature to curb unfair means in examinations without delay. The immediate enforcement ensured that preventive measures were legally binding from the very date of enactment.

स्पष्टीकरण: अनेक अधिनियमों के विपरीत, जिन्हें लागू करने के लिए सरकारी अधिसूचना की आवश्यकता होती है, इस अधिनियम की धारा 1(3) कहती है कि यह तत्काल लागू होगा। यह विधायिका की तात्कालिकता को दर्शाता है कि परीक्षाओं में अनुचित साधनों को बिना विलंब रोका जाए। तत्काल प्रवर्तन से यह सुनिश्चित हुआ कि अधिनियम की रोकथाम संबंधी व्यवस्थाएँ उसी दिन से कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गईं।

3. According to Section 2(a) of the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 1992, what does the term "examination centre" include? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 की धारा 2(क) के अनुसार "परीक्षा केंद्र" में क्या सम्मिलित है?

(A) Only the classroom where exam is held
केवल वह कक्षा जहाँ परीक्षा होती है
(B) Any place fixed for holding public examination including entire premises / कोई भी स्थान जो सार्वजनिक परीक्षा हेतु निर्धारित हो तथा उससे जुड़ा संपूर्ण परिसर
(C) Only government schools
केवल सरकारी विद्यालय

Sample Preview

1. Under the Rajasthan Public Examination Act, 2022, what is the extent of the Act? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 की सीमा क्या है?

(A) Only Jaipur District
केवल जयपुर जिला

(B) Entire State of Rajasthan
सम्पूर्ण राजस्थान राज्य

(C) Only State Government Departments
केवल राज्य सरकार के विभाग

(D) Only Autonomous Bodies
केवल स्वायत्त निकाय

Ans: (B)

Explanation: The Act clearly states that it shall extend to the whole of the State of Rajasthan. This means its applicability is not limited to a particular district, department, or authority. It covers all recruitment examinations conducted under the State Government, including autonomous bodies, boards, and corporations. The purpose is to ensure uniformity in preventing unfair means across the entire state.

स्पष्टीकरण: अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगा। इसका अर्थ है कि यह किसी विशेष जिले, विभाग या प्राधिकरण तक सीमित नहीं है। यह राज्य सरकार के अधीन सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होता है, जिनमें स्वायत्त निकाय, बोर्ड और निगम भी शामिल हैं। उद्देश्य है कि पूरे राज्य में अनुचित साधनों की रोकथाम समान रूप से हो।

2. When does the Rajasthan Public Examination Act, 2022 come into force? / राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 कब लागू होता है?

(A) From the date of Governor's assent
राज्यपाल की स्वीकृति की तिथि से

(B) From the date of publication in Gazette
राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से

(C) From the date notified by State Government
राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से

(D) Immediately after passing by Legislature
विधानमंडल द्वारा पारित होते ही

Ans: (C)

Explanation: The Act does not automatically come into force upon assent or publication. Section 1(3) specifies that it shall come into force on such date as the State Government may appoint by notification in the Official Gazette. This provision gives flexibility to the government to decide the commencement date, ensuring administrative preparedness before implementation.

स्पष्टीकरण: यह अधिनियम स्वीकृति या प्रकाशन के साथ स्वतः लागू नहीं होता। धारा 1(3) में कहा गया है कि यह उस तिथि से लागू होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी। यह प्रावधान सरकार को कार्यान्वयन से पहले प्रशासनिक तैयारी सुनिश्चित करने हेतु लचीलापन प्रदान करता है।

3. According to Section 2(a) of the Rajasthan Public Examination Act, 2022, the term "conduct of public examination" includes which of the following? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2022 की धारा 2(क) के अनुसार "सार्वजनिक परीक्षा का संचालन" में क्या सम्मिलित है?

(A) Only printing of question papers / केवल प्रश्नपत्रों की छपाई

(B) Only evaluation of answer sheets
केवल उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

(C) Preparation, printing, transportation, evaluation, declaration of result, etc.
तैयारी, छपाई, परिवहन, मूल्यांकन, परिणाम घोषणा आदि

(D) Only supervision during exam
केवल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षण

Ans: (C)

Explanation: The Act defines "conduct of public examination" broadly to cover every stage of the examination process. It includes preparation, printing, coding, storing, transporting, distributing, collecting, evaluating,

Sample Preview

LINKING PUBLICATION

is available at

www.LinkingLaws.com >> Linking Publication

Linking Charts

- Diglot Technical Words*
- Important Sections Marking
- Easy Way for Legal Meditation
- Section Linking
- Keywords Highlight
- Charts Wall Tapping
- Major Laws Bird View

Alpha Minor Linking Charts
(Set of 4 Charts)
Criminal Minor Laws
Civil Minor Laws
Alpha Linking
Doctrines
Legal Maxims

All Major Laws Linking Charts
(Set of 5 Charts)
Constitution of India
Civil Procedure Code, 1908
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

New Criminal Major Laws
(Set of 2 Charts)
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

Linking Bare Act

- Criminal Major Laws 2023 (BNS, BNSS, BSA)
- Constitution of India
- Criminal Minor Laws
- Civil Minor Laws
- CPC, 1908
- Local Laws
- Family Laws
- IT Act, 2000
- A&C Act, 1996
- Environmental Laws
- Advocate Act, 1961
- Land Acquisition, 2013
- AIBE Additional Bare Acts
- Consumer Protection Act, 2019
- Transfer of Property Act, 1882
- Specific Relief Act, 1963
- NDPS Act, 1985
- PCPNDT Act, 1994
- Food Safety & Standards Act, 2006
- Motor Vehicles Act, 1988
- Indian Contract Act, 1872
- Labour & Industrial Law
- NI Act, 1881

and many more

Diglot Edition*

ALL-IN-ONE PAPERATHON©

For Preliminary, Mains & Interview

Covered more than 15 States' Judiciary Exams.
Available in English and Hindi Edition

Paperathon® Booklet

Unique Features

1. Sections Switching Table
2. Subject wise Division
3. Cut-Off (Result) Analysis
4. Chapter Wise Bifurcation
5. State Wise PYQ Coverage
6. Subject Weightage Analysis
7. Linked Provision & Explanation
8. Diglot Edition

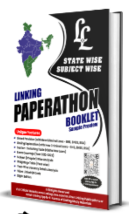

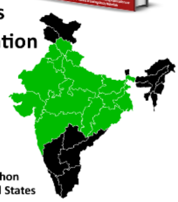

Paperathon Booklet is smart analysis of all questions covered in previous papers of judiciary exam.

Paperathon Covered States

E-Study Material for Judiciary and Law Exams is available at **Linking App.**

Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com

www.LinkingLaws.com

Sample Preview